SPEED POST / E-MAIL

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 5855/2019/21-ब(एक)

भोपाल, दिनांक 8-11-2019

प्रति,

माननीय रजिस्ट्रार जनरल,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
जबलपुर

विषय :- Permission for drawl of salary of surplus secretary to judges from the vacant post of administrative officers.

संदर्भ :- आपका ज्ञापन क्रमांक बी/5268 दिनांक 21-10-19

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है :-

"विभागीय प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि जब 97 प्रायवेट सेक्रेटरी कार्यरत थे जब ऐसी स्थिति में प्रायवेट सेक्रेटरी के स्वीकृत 34 पदों का समर्पण प्रशासकीय विभाग द्वारा क्यो किया गया। विभाग को पूर्व से कार्यरत 20 प्रायवेट सेक्रेटरी का वेतन आहरण एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (ज्यूडीशियल) के समकक्ष रिक्त पदों के विरूध्द कराने की सहमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (ज्यूडीशियल) के उक्त रिक्त 20 पदो को स्थगन में रखा जाएगा एवं इन पदों पर कोई भर्ती/ पदोन्नति नहीं की जाएगी।"

8/11/19

(रूपम वेदी)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

11 NOV 2019

Reg. (A)

Asstt. Reg. (E)

SO(RR)

Meenakshi
13-11-19

Scanned by CamScanner

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक C 4884 /   जबलपुर दिनांक 20 11/2019

प्रतिलिपि -

1. रजिस्ट्रार (प्रशासन) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
2. [illegible] अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
3. आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल
4. [illegible] एकाउन्टस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
5. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
6. डिप्टी रजिस्ट्रार/ऑफिसर [illegible] लेखा, बजट, पेंशन उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
7. प्रभारी अधिकारी, [illegible] कोष एवं लेखा जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर
8. सहायक रजिस्ट्रार [illegible], उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न - मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के पत्र क्र. 5855/2019/21-ब(एक) भोपाल दि. 08.11.2019 की प्रतिलिपि

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)